वर्ष :: 33 अंक : 35
पृष्ठ : 08 :: मूल्य 2 रुपए मात्र

प्रकाशन का 33 वां वर्ष

/mithilavarnan

मिथिला वर्णन

स्वच्छ पत्रकारिता, स्वस्थ पत्रकारिता

झारखंड-बिहार का लोकप्रिय हिन्दी साप्ताहिक

पूरे परिवार के लिये आध्यात्मिक पत्रिका

अवश्य पढ़ें-

निखिल-मंत्र-विज्ञान

14ए, मेनरोड, हाईकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर (राज.)
फोन : (0291) 2624081, 263809

बोकारो :: रविवार, 28 मई, 2023 News & E-paper : www.varnanlive.com E-mail : mithilavarnan@gmail.com

बेलगाम माफियागिरी, बेखौफ हौसले

कार्यालय संवाददाता

बोकारो : बोकारो इस्पात नगर और इसके उपशहर चास में भू-माफियाओं के काले कारनामे हमेशा से ही चर्चा का विषय बने रहे हैं। जमीन के सौदागरों ने स्वार्थपूर्ति के लिए प्रकृति को भी खतरे में डाल दिया है। नदी, नाला, पहाड़, सब के सीने काट-काटकर माफियाओं की माफियागिरी पांव पसार चुकी है। आशियाने दिलाने, प्लॉट आवंटित कराने जैसे प्रलोभनों के नाम पर ठगी के मामले तो सुर्खियों में रहे ही हैं, परंतु अब आदिवासी-राज में आदिवासियों की जमीन की खुली लूट और इस लूटपाट में खूनी खेल भी आम बात हो चली है। पिछले दिनों जिस कदर चौरा बस्ती में सुरेश मुर्मू नामक एक संताली नेता की हत्या जमीन-विवाद में कुछ दबंगों ने कर दी, उसने सिस्टम पर एक बार फिर बट्टा लगा दिया है। हाल के दिनों में चास अंचल में जमीन का विवाद बढ़ा है और भूमि माफियाओं का वर्चस्व भी बढ़ाता देखा जा रहा है। एनएच-23 फोरलेन सड़क वर्ष 2011 में बनकर तैयार होने के बाद तेलीडीह, चौरा, कमलडीह, बांधगोड़ा, पिपराटांड आदि में भू-माफियाओं के वर्चस्व में काफी इजाफा देखा जा रहा है। आए दिन मारपीट व दबंगई की घटनाएं भी सामने आती हैं। इसी कड़ी में बीते 19 मई को चास की शिवपुरी कॉलोनी में फुदनीडीह के रहने वाले विष्णु शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पांच दिन बाद ही 24 मई को चौरा बस्ती के रहने वाले सुरेश मुर्मू को जमीन माफियाओं ने मौत के घाट उतार दिया। सुरेश को बाद में उसी जमीन के हिस्से में दफनाया गया, जिस जमीन के हिस्से के लिए उसकी हत्या कर दी गई। यहां सबसे आश्चर्य की बात पुलिस और प्रशासन की शिथिलता है। पुलिस के समय पर कार्रवाई न करने के कारण भू-माफियाओं के नापाक हौसले और बुलंद हो जाते हैं। बताया जाता है कि चौरा बस्ती के जमीन विवाद की सूचना मृतक सुरेश मुर्मू ने 15 दिन पहले डीसी को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जब जमीन पर विरोध शुरू किया, तो सुरेश की हत्या हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

सेगेंल अभियान ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

पिंड्राजोरा थाना अंतर्गत चौरा बस्ती में जमीन विवाद को ले मारपीट में एक की मौत के मामले में आदिवासी सेंगेल अभियान ने आक्रोश व्यक्त किया है। बोकारो जिला सेंगेल अध्यक्ष सुखदेव मुर्मू ने कहा कि घटना के (शेष पेज- 7 पर)

जेल जानेवालों में पुलिसकर्मी भी

चौरा गांव में 24 मई को हुए जमीन विवाद में मुख्य भूमिका पुलिस बल के एक सिपाही सुखवंत सिंह की सामने आई। सुरेश कुमार मुर्मू की मौत के अगले ही दिन ग्रामीणों ने घटनास्थल के निकट एनएच-23 स्थित चौरा बस्ती के पास सड़क जाम कर दिया। करीब छह घंटे तक जाम जारी रहा। इस संबंध में 12 नामजद व 15 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने चार आरोपियों- बोकारो पुलिस बल का सिपाही सुखवंत सिंह, सेक्टर-12 निवासी मंतोष रंजन, तेलीडीह साईट के राहुल कुमार और बांधगोड़ा साईट निवासी चरणदास महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर खबर लिखे जाने तक पुलिस छापेमारी कर रही थी।

समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं, आम बात हो गई गोलीबारी

उल्लेखनीय है कि बोकारो में जमीन हड़पने का मकसद पूरा नहीं होने या इसमें किसी भी प्रकार का रोड़ा आने की स्थिति में भू-माफिया अपने भाड़े के गुर्गों से जब चाहें, तब गोली चलवाकर दहशत फैला देते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अकेले चौरा बस्ती में तीन बार गोली चलने की घटना जमीन विवाद में हो चुकी है। पिंड्राजोरा पुलिस ने वर्ष 2020 में खेत में फेंकी गई एक पिस्टल भी बरामद की थी। जबकि, दो महीना पहले ही सेक्टर-12 थाना क्षेत्र स्थित बारी-को-ऑपरेटिव में फायरिंग हुई थी। इस मामले में को-ऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके अलावा सोलागीडीह में भी जमीन के लिए फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी। इसमें चास मुफस्सिल थाना पुलिस ने रांची के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दूसरी तरफ, जमीन दिखाकर लाखों रुपए ठगी के मामले भी जिले के विभिन्न थानों में लगातार बढ़ी है। भू-माफिया जमीन दिखाकर एडवांस के तौर पर लाखों रुपए ले लेते हैं, लेकिन जब रजिस्ट्री करने की बारी आती है, तो पीड़ितों को बरगलाया जाता है। ऐसे में पीड़ित जब थाना शिकायत लेकर पहुंचता है, तो कार्रवाई भी नहीं होती है। जाहिर है, ऐसे में उनका मनोबल बढ़ेगा ही और यही मनोबल धीरे-धीरे बेखौफ हौसलों में तब्दील हो जाते हैं। नतीजतन, ऐसी ही गोलीबारी होती है। सूत्रों के अनुसार चास अंचल से एक जमीन पर कई लोगों की जमाबंदी कर रसीद निर्गत कर दी जाती है। इसके कारण रैयत चाहे सीएनटी के हों, या खतियानधारी, भूमि माफियाओं के आगे बेबस नजर आते हैं। पुलिस की शरण में जाते हैं, तो पुलिस भी हाथ खड़े कर देती है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। भू-माफियाओं के खिलाफ चास, चास मुफस्सिल व पिंड्राजोरा थाना में सबसे अधिक मामले दर्ज होते हैं। बीते अप्रैल माह में 9 मामले दर्ज हुए हैं।

एसडीपीओ बोले- पुलिस शांति-व्यवस्था बनाने को प्रयासरत

चास के अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) पुरुषोत्तम कुमार सिंह का जमीन-विवाद मामलों को लेकर कहना है कि पुलिस शांति-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रयासरत है। हत्या जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी कोशिश की जा रही है। जमीन के कागजातों की जांच कराने में चूंकि पुलिस असक्षम है, ऐसे में अंचल कार्यालय से जांच करायी जाती है, ताकि पता चले कि जमीन किसकी है। भू-माफियाओं को कभी भी थानों में शरण नहीं दिया गया है और न ही पुलिस उनके आगे बेबस है। उन्होंने दावे के साथ कहा है कि जमीन का विवाद हो या जमीन की ठगी का, सभी मामलों में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

कब्जा-मुक्त कराएंगे आदिवासियों की जमीन : अपर समाहर्ता

जिले के अपर समाहर्ता (एसी) सादात अनवर ने कहा - जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ था, वह जमीन आदिवासी खाते की है। स्पष्ट रिपोर्ट आने के बाद चौरा गांव में जिन आदिवासी परिवारों की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, उसे कब्जा मुक्त करते हुए आदिवासी परिवारों को उनकी भू-वापसी शुरू होगी।

यूपीएससी डीपीएस बोकारो, चिन्मय विद्यालय और अयप्पा के विद्यार्थी रह चुके हैं सफल अभ्यर्थी, विद्यालय परिवार में हर्ष

राष्ट्रीय फलक पर फिर चमके बोकारो के सितारे

कार्यालय संवाददाता

बोकारो : संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में बोकारो के चार पूर्व विद्यार्थियों ने शानदार कामयाबी हासिल कर इस्पातनगरी का मान एक बार फिर बढ़ाया है। देश की सर्वप्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज की परीक्षा में राष्ट्रीय फलक पर इनकी प्रतिभा की चमक सामने आई है। तीन विभिन्न विद्यालयों के पूर्व विद्यार्थियों के अलावा बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) के एक अधिकारी ने भी कामयाबी पाई है। चिन्मय विद्यालय के 2013-2015 बैच के छात्र अविनाश कुमार ने यूपीएससी के नतीजों में ऑल इंडिया रैंक 17 हासिल कर सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अति सामान्य परिवार से संबंधित किसान पुत्र अविनाश कुमार बचपन से ही कुशल बुद्धि एवं विलक्षण प्रतिभा के स्वामी रहे हैं। उन्होंने 12वीं की परीक्षा में 93.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किया तथा देश के प्रतिष्ठित जादवपुर यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और वहां से सफलता प्राप्त की। अविनाश ने बताया कि यूपीएससी की परीक्षा में वह दो बार शामिल हुआ, लेकिन असफल रहा। इसके बाद भी हार नहीं मानी और तीसरी बार परीक्षा में शामिल हुआ। नतीजा सबके सामने है। विद्यालय की 2015 बैच की कला संकाय की छात्रा श्रुति ने भी 506वां रैंक यूपीएससी में कामयाबी पाई है। ज्ञात हो कि 2 वर्ष पहले चिन्मय विद्यालय बोकारो के छात्र शुभम कुमार ने यूपीएससी में भारत में प्रथम रैंक प्राप्त किया था। उसी वर्ष विद्यालय की ही छात्रा जया ने भी कामयाबी पाई थी। विद्यालय अध्यक्ष बिश्वरूप मुखोपाध्याय, सचिव महेश त्रिपाठी एवं प्राचार्य सूरज शर्मा सहित समस्त विद्यालय परिवार ने अविनाश और श्रुति को बधाई देते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना की है।

इधर, डीपीएस बोकारो के 2018 बैच के छात्र शुभम ने 41वां रैंक पाकर अपने स्कूल का नाम रोशन किया। मधुबनी (बिहार) के खुटौना निवासी शुभम विज्ञान के साथ स्कूल से पास हुए थे और नई दिल्ली में सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे थे। डीपीएस बोकारो के प्राचार्य एएस गंगवार ने कहा कि यह न केवल शुभम या स्कूल के लिए, बल्कि झारखंड के लिए भी एक उपलब्धि है। इसी प्रकार श्री अयप्पा पब्लिक स्कूल के पूर्व छात्र अभिनव प्रकाश ने यूपीएससी में 279वां रैंक लाकर स्कूल का मान बढ़ाया। चतरा के अभिनव प्रकाश 2017 में अयप्पा पब्लिक स्कूल के छात्र थे। वहीं, बीएसएल के कर्मचारी कुमार रजत ने 423वां रैंक हासिल किया है। बोकारो स्टील टाउनशिप निवासी रजत बीएसएल के निदेशक प्रभारी के कार्यालय में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं।

– संपादकीय –

लोकतंत्र के मंदिर पर सियासत अनुचित

देश के नए संसद भवन के मुद्दे पर देशभर में खूब सियासत हो रही है। कांग्रेस सहित 19 दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। कारण यह है कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों करना तय किया गया, जबकि विपक्षी दलों के मुताबिक यह काम राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री सदन का हिस्सा और शासन प्रमुख होने के नाते अक्सर विपक्ष के निशाने पर रहते हैं और उन्हें उस तरह की निर्विवाद हैसियत हासिल नहीं होती, जो संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के नेता लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। सरकार का अपना पक्ष है और उनके अपने तर्क हैं, लेकिन विपक्ष की भी अपनी शिकायतें हैं। भाजपा नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को देश के लिए गौरव का पल मानते हुए जश्न मना रही है। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। देश के राजनीतिक दलों में इस मुद्दे को लेकर दो फाड़ हो गया। मसला एनडीए बनाम यूपीए तो है ही, लेकिन कुछ विपक्षी दल भी भाजपा के साथ भी जा खड़े हुए हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर कुल 16 दल भाजपा के साथ आ गए हैं। इन दलों में बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट), नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल - सोनीलाल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तमिल मनीला कांग्रेस, अन्नाद्रमुक, आजसू (झारखंड), मिजो नेशनल फ्रंट, वाईएसआरसीपी, टीडीपी, बीजद और शिरोमणि अकाली दल शामिल हैं। संसद के उद्घाटन कार्यक्रम के समर्थन में जो दल एक साथ आए हैं, अगर संसद में इनकी सीटों का गणित देखा जाए तो लोकसभा में उनकी कुल ताकत 366 और राज्यसभा में 120 है। लोकसभा में सिटिंग सदस्यों की संख्या 545 और राज्यसभा में 238 है। यानी मौजूदा समय में एनडीए के पास लोकसभा का 67.15% और राज्यसभा का 50.42% समर्थन साथ है। यह भी उल्लेखनीय है कि देश राष्ट्रपति प्रणाली से संचालित नहीं होता। हमारी प्रणाली संसदीय है और प्रधानमंत्री इसके प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री ही देश के सर्वोच्च प्रत्यक्ष निर्वाचित जन-प्रतिनिधि भी हैं। वह भारत सरकार के कार्यकारी प्रमुख भी हैं। देश की तमाम गतिविधियों, परिस्थितियों, नीतियों और कूटनीति आदि का प्रथम दायित्व भी प्रधानमंत्री पर ही है। लोकतांत्रिक जनादेश का प्रचंड बहुमत भी उन्हें ही हासिल है, लिहाजा उनके कुछ विशेषाधिकार भी हैं। स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ही ऐतिहासिक लालकिले से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति सामूहिक परेड की सलामी लेते हैं, क्योंकि वह तीनों सेनाओं के 'सुप्रीम कमांडर' भी हैं। यह विवाद का विषय नहीं होना चाहिए कि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर 'संसद' का उद्घाटन राष्ट्रपति करें अथवा प्रधानमंत्री करें। दरअसल, इसे विशुद्ध राजनीति का मुद्दा बना दिया गया है। कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार को नए संसद भवन के निर्माण पर आपत्ति थी और अब उद्घाटन को भी विवादित बनाया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा, जिसमें संसद भवन भी है, का खर्च 20,000 करोड़ रुपए प्रचारित कर देश को गुमराह करने की कोशिश की गई। उसे 'मोदी महल' करार दिया गया। उसे प्रधानमंत्री का 'अंधा अहंकार' तक बताया गया। 'आपराधिक बर्बादी' सरीखे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री की निजी महत्त्वाकांक्षा को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च अदालत में चुनौती देने की कोशिश की गई। कांग्रेस यह भूल गई कि यूपीए सरकार के दौरान लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के कार्यकाल में, नए संसद भवन की जरूरत का आकलन किया गया था। कांग्रेस को उद्घाटन की तारीख 28 मई पर भी आपत्ति है, क्योंकि उस दिन 'सावरकर जयंती' है। जबकि, गांधी परिवार तो महान क्रांतिकारी सावरकर को 'स्वतंत्रता सेनानी' मानने को तैयार नहीं है, लिहाजा अलग-अलग दलीलें दी जा रही हैं। कुल मिलाकर, लोकतंत्र के नए मंदिर पर सियासत ने एक बार देश में ओछी राजनीति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

यूपीएससी : फिर बेटियों की बादशाहत

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नतीजे बीते दिनों जारी कर दिए। नतीजों मे इस बार फिर से लड़कों की अपेक्षा लड़कियों ने इस सर्वोच्च परीक्षा मे अपनी बादशाहत कायम की है। यूपीएससी 2021 में जहां प्रथम तीन स्थान लड़कियों ने हासिल किए थे, वहीं इस बार आयोग की अंतिम सूची में प्रथम चार स्थान बेटियों ने पुनः हासिल किए हैं, जो भारत जैसे देश के लिए अपने-आप में बहुत कुछ बयां करता है। यह करारा जवाब उस मानसिकता के लिए भी खास है, जो आज भी हर कार्य को यहां पुरुष व महिला में विभाजित करते हैं। बेटियों की यह सफलता खास इसलिए भी है, क्योंकि देश में आज भी कई लोग लिंगानुपात पर अपने ठेकेदारी जमाने पर तुले हैं। भारत मे करोड़ों लोग आज भी अपनी बेटी को उच्च शिक्षा प्रदान करने से कतराते हैं। ऐसे में लोक सेवा आयोग द्वारा जारी नतीजों पर गौर फरमाना लाजमी हो जाता है। बेटियों ने अपने परीक्षा परिणाम के जरिये यह बताने का प्रयास किया है कि देश में आज पुरुष और महिला के बीच की खाई काफी हद तक भर चुकी है। यूपीएससी 2022 के परिणामों में इस बार शीर्ष स्थान ग्रेटर नोएडा स्थित जलवायु विहार सोसायटी की इशिता किशोर ने अर्जित किया है।

बगैर कोचिंग के सफलता एक प्रेरणा

बिटिया की सफलता अहम इसलिए है, क्योंकि उन्होंने यह सर्वोच्च मुकाम बिना किसी कोचिंग के प्राप्त किया है। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके के साथ घर पर पढ़कर ही यह बहुमूल्य उपलब्धि हासिल की है, जो देश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणादायी साबित हो सकती है। परीक्षा के लिए महंगी कोचिंग लेना हर विद्यार्थी के लिए संभव नहीं होता, परंतु घर पर सेल्फ स्टडी करना सब के बस की बात हो सकती है। अर्थशास्त्र ऑनर्स में स्नातक करने के उपरांत इशिता ने सिविल सेवा के बारे में विचारा और वैकल्पिक विषय के लिए राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय चुना और तन्मयता से विषयों की गहराई को तौलती रहीं। हमें उनकी यह सफलता सामान्य उपलब्धि लग सकती है, परंतु इशिता के लिए यह बेहद विशेष है, क्योंकि उन्हें यह सफलता तीसरे प्रयास के वर्षों की मेहनत के उपरांत हासिल हुई है। न्यूज चैनल को दिए अपने पहले साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मेरे परिवार ने मुझे यूपीएससी के लिए हर वक़्त असीम समर्थन दिया। मैं प्रीलिम्स में दो बार असफल हुई, बावजूद इसके परिवार को मुझ पर विश्वास था और मेरा मनोबल बढाता रहा, जिसके लिए मैं उनकी सदा आभारी रहूंगी।

बिहार की 'गरिमा'

इसी तरह बक्सर की गरिमा लोहिया ने देश की इस प्रमुख परीक्षा में दूसरा रैंक हासिल करके दिखा दिया कि यदि हौसले बुलंद हों तो सफलता तय है। गरिमा ने अपनी इस विशेष उपलब्धि से जहां यूपीएससी में बिहारियों की बादशाहत को बरकरार रखा है, वहीं उन्होंने अपने स्वर्ग सिधार चुके पिताजी की आत्मा को भी शीतलता प्रदान की है। फलस्वरूप आज उनके परिवार के साथ-साथ संपूर्ण बिहार राज्य गदगद है। एक समय अपने पिता के बिछड़ने से वीरान गरिमा के सपने बुरी तरह से टूट रहे थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को वक्त दिया, समाज को देखा व समझा और पुनः परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करने में जुट गई। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने उनके सपनों को झकझोर दिया था। फलस्वरूप उनकी मेहनत बेहद प्रभावित हुई है तथा ऑनलाइन कोर्सेज से तैयारी यदाकदा जारी रखी। परंतु, वक्त बदलने के साथ

उन्होंने अपने मेहनत के घंटों में इजाफा किया और विषयों में पकड़ को मजबूत करती गई। नतीजतन, उन्हें देश की प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल हुई। उन्होंने आगे कहा कि वे अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को देतीं हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी के साथ साथ मां उनका मजबूती से साथ देती रहीं।

उमा हरति की कामयाबी भी खास

लोक सेवा आयोग के इस बार के परिणाम मे तीसरे स्थान पर रहने वाली तेलंगाना राज्य की उमा हरति के चर्चे भी आम हैं। आईआईटी हैदराबाद से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद बेटी ने आईएएस की राह चुनी। गहनता से अध्ययन शुरू किया। इस बीच उन्होंने सिविल सेवा कोचिंग संस्थान में भी छह महीनों तक ऑनलाइन कार्य किया, लेकिन उनका लक्ष्य यूपीएससी था। इसलिए, उन्होंने वक्त रहते नौकरी त्याग दी और जी-जान से तैयारियों में जुट गई। इसके उपरांत वर्ष 2023 के 23 मई की वह दोपहरी आई, जिसने कहा कि उमा हरति एन ने यूपीएससी में तीसरा रैंक अर्जित किया है। परिणामस्वरूप, उमा के लिए पूरा तेलंगाना गौरवान्वित महसूस होने लगा।

प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी बनी स्मृति की प्रेरणा

जबकि, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली स्मृति मिश्रा ने सूची में चौथी रैकिंग पाई है। मिरांडा हाउस कॉलेज के लाइफ सांइस डिपार्टमेंट की छात्रा रही स्मृति ने इस प्रमुख परीक्षा के लिए ऑप्शनल विषय के रूप मे जीव विज्ञान चुना और बारीकी से इसका अध्ययन करती रही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मैने अपने शिक्षकों और सीनियर्स से काफी मदद ली। फलस्वरूप उन्हें इस प्रमुख परीक्षा मे चौथा रैंक हासिल हुआ। उन्होंने बताया कि वह अपने डीएसपी पिता की कार्यशैली से बेहद प्रभावित हैं। नोएडा की प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को प्रेरणा-स्रोत मानती हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे देश में महिलाओं के उत्थान के लिए वह हरसंभव प्रयास करेगी। उनका मानना है कि देश की महिलाओं के पास तजुर्बा है, पर उन्हें अवसरों का अभाव रहता है।

समाज के ठेकेदारों को सबक

इस तरह हम कह सकते हैं कि विगत दो वर्षों से इस सर्वोच्च परीक्षा की मैरिट में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का दबदबा रहा है, जो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह उन समाज के ठेकेदारों के लिए कड़ा सबक है, जो आज भी बेटियों की शिक्षा पर सवाल खड़े करते हैं, जो आज भी बेटियों को घर से बाहर निकलने के लिए अनेक रुकावटें खड़ी करते हैं, जो आज भी महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु मात्र मानते हैं। बहरहाल, देश की उक्त बेटियों ने जो किया है, वह सहज नहीं है। इनकी सफलता से आज संपूर्ण राष्ट्र गदगद है। हम उनके लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

– सुरेन्द्र कुमार
स्वतंत्र लेखक एवं विचारक, मंडी (हिमाचल प्रदेश)।

कुटिलता-सने प्रतिरोधी स्वरों के विरुद्ध

सृजन-क्षेत्र में बहुत दिनों से
सुना है हमने - 'प्रतिरोधी स्वर'!
आज आइए, समझें इसको
गहराई से
विश्लेषण कर...

(1)
प्रतिरोधी स्वर का प्रतिरोध
गाने लगे 'क्रांति गान'
यदि
शुद्ध सत्य के विरुद्ध,
ईमानदारी के विरुद्ध
जलाने लगे मशाल यदि वह,
संतोष के विरुद्ध भड़काए
लिप्सा की भयानक लौ को
सिखाने लगे घृणित हिंसा
अहिंसकों को...
- तो ऐसे अस्वीकार्य विचारों का
स्वर बनना अवांछनीय है-
गले में ही अटकना उचित है
दुरभि संधि में सराबोर स्वरों का
दफन हो जाना-
पतन हो जाना उचित है...

(2)
क्या निर्मल सदाशयता के विरुद्ध
होना चाहिए
कोई प्रतिरोधी स्वर?
क्या पौरुष और शौर्य के विरुद्ध
होना चाहिए
कोई प्रतिरोधी स्वर?
क्या सुसंस्कारों के विरुद्ध भी कोई
प्रतिरोधी स्वर
स्वीकार्य होना चाहिए हमें?
क्या स्वीकार्य होना चाहिए कोई
प्रतिरोधी स्वर
सुखद शांति के विरुद्ध?
प्रतिरोधी स्वर चाहिए क्या
राष्ट्र की समेकित उन्नति के
विरुद्ध?... देखना होगा
पूछना होगा... ये प्रतिरोधी स्वर
कैसे हैं भाई?
कहाँ से आए हैं?
लगातार आते हैं?
क्यों हमें भरमाने को
किसिम-किसिम के गीत गाते
हैं...?

(3)
प्रतिरोधी स्वरों का
ऊँचा होना जरूरी है
भ्रष्टाचार के विरुद्ध,
बहुत ऊँचा होना जरूरी है
प्रतिरोधी स्वरों का
घृणित कुटिलता के विरुद्ध-
मक्कारी के विरुद्ध,
प्रतिरोधी स्वर चाहिए बहुत सारा
हमें
अकर्मण्य दोहरे चरित्रों के विरुद्ध,
प्रतिरोधी स्वर अवश्य चाहिए
सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध-
जातिवाद के विरुद्ध
धार्मिक उन्माद के विरुद्ध
सभी प्रदूषणों के विरुद्ध
अनैतिकता के विरुद्ध
कायरता के विरुद्ध...
दसों दिशाओं को साक्षी रखकर
स्वागत करता हूँ
मुखर होकर
ऐसे सारे स्वीकार्य और समाज के
हितकर
प्रतिरोधी स्वरों का
खुला है झरोखा-
खुला है झरोखा...

- कुमार मनीष अरविंद

आप अपने विचार अथवा अपनी रचनाएं हमें ई–मेल पर भेज सकते हैं– mithilavarnan@gmail.com, Contact : 9431379234 **Visit us on : www.varnanlive.com**
Join us on /mithilavarnan
(किसी भी कानूनी विवाद का निबटारा केवल बोकारो कोर्ट में हीं होगा।)

आदर्श पंचायत बनेगी कुसुमकियारी, मिलेंगी सभी सुविधाएं

गुड न्यूज... सांसद आदर्श ग्राम योजना, फेज- 2 के तहत होंगे कई काम; खाका तैयार

मॉडल स्कूल बनेंगे आठ विद्यालय : डीसी

मौके पर अपने संबोधन में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि कुसुमकियारी का चयन सांसद आदर्श ग्राम के तहत किया गया है। इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए सभी कार्यों को किया जाएगा। पंचायत अंतर्गत आठ विद्यालय हैं, जिसमें लगभग 900 छात्र अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। लर्निंग म्यूजियम के तहत विद्यालयों को आकर्षित बनाया जाएगा, ताकि बच्चों की रूचि विद्यालय आने एवं पठन-पाठन में हो। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता होगी, पेयजल सुविधा व सोलर जलापूर्ति आदि का अधिष्ठापन किया जाएगा। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन नहीं है, उन केंद्रों को अगले छह माह में अपना भवन उपलब्ध कराया जाएगा। कुसुमकियारी में अपना पंचायत भवन नहीं है, जल्द डीएमएफटी के तहत पंचायत भवन का निर्माण शुरू करवाया जाएगा। वहीं, मोबाइल नेटवर्किंग व इंटरनेट आदि की भी सेवा को बेहतर किया जायगा। डीसी ने कहा कि पूरे पंचायत क्षेत्र का सर्वे कराकर प्राथमिकता के तहत सड़क व आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों में परिसंपत्ति भी बांटी गई।

संवाददाता
बोकारो : चंदनकियारी प्रखंड की कुसुमकियारी पंचायत को धनबाद सांसद पीएन सिंह ने सांसद आदर्श ग्राम योजना (फेज टू) के तहत अंगीकृत किया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय चंडीपुर परिसर में प्रवेश बिंदु गतिविधि एवं जागरूकता पीढ़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मौके पर सांसद श्री सिंह के साथ उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त कीर्तिश्री जी, जिला परिषद सदस्य सुषमा देवी, सांसद प्रतिनिधि आरएन ओझा, चंदनकियारी विधायक प्रतिनिधि विनोद गोराई, प्रखंड प्रमुख, मुखिया, उप प्रमुख आदि उपस्थित थे। अपने संबोधन में सांसद ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम का उद्देश्य एक आदर्श गांव व पंचायत का निर्माण करना है। चंदनकियारी प्रखंड के कुसुमकियारी पंचायत का चयन सांसद आदर्श ग्राम के तहत किया गया है। आने वाले दिनों में यहां सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएगी। पूरे पंचायत क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। वह स्वयं यहां होने वाली कार्य प्रगति की निगरानी एवं पंचायत का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लेंगे।

इस दौरान सांसद ने उपायुक्त समेत पूरी टीम की प्रशंसा की और जिला प्रशासन के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया।

विडंबना शोभा की वस्तु बनी है बीएस सिटी रेलवे स्टेशन की स्वचालित सीढ़ी, यात्रियों को परेशानी

स्टेशन क्लास वन, व्यवस्था थर्ड क्लास

संवाददाता
बोकारो : बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन। आद्रा मंडल का क्लास वन का स्टेशन। लेकिन, व्यवस्था थर्ड क्लास से भी चौपट। कोई बुजुर्ग, बीमार या दिव्यांग यात्री यहां से प्लेटफॉर्म नंबर-2 से सफर करने के लिए जाय या यहां सफर कर पहुंचे, तो उसे प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर आने में जो दिक्कत होती है, वह क्लास वन के स्टेशन के लिए बेहद शर्मनाक है। यहां की स्वचालित सीढ़ी महज शोभा की वस्तु बनी है। बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर- 2 से 1 की ओर जाने वाले यात्रियों को बगैर एस्केलेटर आने-जाने में काफी परेशानी होती है। प्लेटफार्म नंबर 2 पर अक्सर एस्केलेटर रुका ही रहता है। वैसे भी जब से यहां स्वचालित सीढ़ी लगाई गई, तब से अधिकतर समय यह बंद ही पड़ी रहती है। लिहाजा, यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

प्लेटफार्म नंबर 1 से 2 पर जाने के लिए या दो से एक पर आने के लिए उन्हें फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ता है। भारी-भरकम सामान लेकर आने-जाने वाले यात्रियों, बुजुर्गों और खासतौर से बीमार एवं दिव्यांग यात्रियों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसे लेकर रेलवे के अधिकारियों ने अब तक कोई खास गंभीरता नहीं दिखाई है। हर वर्ष रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए रेलवे की ओर से गठित पैसेंजर सुविधा समिति की टीम आती है, लेकिन सदस्यों की नजर परेशानी की ओर नहीं जाती है। इस वजह से समस्या का निदान होता नहीं दिख रहा है। जबकि स्टेशन पर हाल के वर्षों में लोगों का आना-जाना बढ़ा है। इसे देखते हुए सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर न तो यात्री सुविधा समिति के सदस्यों का ध्यान है और न ही रेलवे के अधिकारियों का। लिहाजा, यात्रियों में काफी रोष है।

रोजाना 6000 यात्रियों की होती है आवाजाही

बता दें कि बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन से होकर रोजाना 34 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन होता है और 6000 से अधिक यात्रियों की रोजाना आवाजाही होती है। यहां वर्तमान में तीन प्लेटफार्म हैं और तीनों प्लेटफार्म को जोड़ने के लिए स्टेशन परिसर में मात्र एक ही एस्केलेटर लगाया गया है और वह भी बस शोभा की वस्तु बनी हुई है। रेलवे स्टेशन पर एक नया फुट ओवर ब्रिज भी बना है, लेकिन इसकी उंचाई काफी अधिक है। ब्रिज के साथ लिफ्ट भी लगाया जा रहा है, ताकि यात्रियों को सुविधा हो। लेकिन, यात्रियों का मानना है कि उस स्थान पर एक नया एस्केलेटर सीढ़ी होता तो लोगों को सुविधा होती।

दो नया एस्केलेटर लगने की उम्मीद

आद्रा रेल मंडल के एसडीसीएम विकास कुमार का कहना है कि बोकारो रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग और बीमार यात्रियों की परेशानी को देखते हुए दो नया एस्केलेटर लगाने की तैयारी की जा रही है। आने वाले दिनों में एस्केलेटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। वहीं, खराब एस्केलेटर को भी मरम्मत कर जल्द चालू करवाया जाएगा, ताकि यात्रियों की परेशानी दूर हो सके। अब अधिकारी का यह आश्वासन कब तक धरातल पर उतर पाता है, यह देखना बाकी है।

बीएसएल संचालित स्कूलों में 11वीं कक्षा में नामांकन शुरू

विज्ञान संकाय में दाखिले के लिए 85% व कॉमर्स के लिए 70 % का कट-ऑफ जारी

संवाददाता
बोकारो : बोकारो स्टील द्वारा संचालित सीबीएसई से सम्बद्ध स्कूलों बीआईएसएसएस-2 सी, तथा बीआईएसएसएस-8 बी में ग्यारहवीं कक्षा में एडमिशन के लिए बीएसएल के शिक्षा विभाग द्वारा सूचना जारी की जा चुकी है। बीएसएल द्वारा संचालित स्कूलों से उत्तीर्ण हुए बच्चे अथवा किसी अन्य स्कूल से उत्तीर्ण बीएसएल कर्मचारियों के बच्चे अथवा डीपीएलआर द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र वाले विस्थापित नन-बीएसएल वर्ग के बच्चे इन स्कूलों में एडमिशन के पात्र होंगे। इनके अलावा अन्य स्कूलों, बोर्डों से उच्च अंक के साथ (साइंस स्ट्रीम के लिए 85 प्रतिशत या अधिक, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 70 फीसदी या अधिक, तथा आर्ट्स स्ट्रीम के लिए 50 प्रतिशत या अधिक) अंक प्राप्त करने वाले बच्चे भी एडमिशन के लिए आवेदन दे सकेंगे। बीआईएसएसएस-2 सी एवं बीआईएसएसएस-8 बी में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स विषयों में एडमिशन लिए जाएंगे।

बीएसएल स्कूलों से उत्तीर्ण हुए बच्चे एडमिशन फॉर्म उसी स्कूल में 29 मई-2023 से 10 जून -2023 तक प्राप्त कर सकते हैं। जिस स्कूल से वे पास हुए हैं, अन्य स्कूलों अथवा बोर्डों से पास हुए बच्चों के लिए एडमिशन फॉर्म आगामी 29 मई से 10 जून 2023 तक बीएसएल के शिक्षा विभाग, कमरा नंबर-236, नगर सेवा भवन, बी-ब्लॉक, बी एस सिटी से प्राप्त किया जा सकता है। वैसे बच्चे जो बीएसकेवी- 3डी और बीएसबीवी- 9 बी से पास हुए हैं, वे 29 मई से 10 जून -2023 तक संबंधित स्कूल जहां से वे पास हुए हैं, एडमिशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। संबन्धित स्कूलों में एडमिशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून 2023 को 12 बजे दोपहर तक निर्धारित की गई है।

एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी बीएसएल के शिक्षा विभाग, कमरा नंबर-236 नगर सेवा भवन, बी-ब्लॉक, बी एस सिटी के सूचना पट्ट से प्राप्त की जा सकती है।

नवोदय विद्यालय में चयन परीक्षा 22 जुलाई को

जिले के तेनुघाट स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन आगामी 22 जुलाई 2023 को किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति ज.न.वि. तेनुघाट अध्यक्ष सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जरूरतमंद व अहर्ता पूर्ण करने वाले जिले के छात्रों से तय तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। विद्यालय के प्राचार्य बिपिन कुमार ने बताया कि 11 वीं कक्षा में प्रवेश के लिए सभी सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सत्र 2022-23 एवं 2022 के दौरान जिला के सरकारी, सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों से दसवीं कक्षा का अध्ययन किया होना चाहिए, जिनका जन्म 01 जून 2006 से 31 जुलाई 2008 के बीच हुआ हो, वे आवेदन कर सकेंगे।

अवैध खनन और परिवहन पर रोक के लिए करें नियमित कार्रवाई : डीसी

जिला खनन टास्क फोर्स समिति की बैठक में कार्यों की समीक्षा, दिए गए निर्देश

संवाददाता

बोकारो : जिला समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने गुरुवार को जिला खनन टास्क फोर्स समिति (डीएमटीएफ) की बैठक की। मौके पर पुलिस अधीक्षक चंदन झा, जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार सिंह, एसडीओ बेरमो अनंत कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार आदि उपस्थित थे। उपायुक्त श्री चौधरी ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की क्रमवार समीक्षा की। जिला खनन पदाधिकारी श्री कुमार ने की गई अनुपालन कार्रवाई के संबंध में बताया। उपायुक्त ने जिला खनन टास्क फोर्स कमेटी (डीएमटीएफ), अनुमंडल/अंचल कमेटी (एसडी/सीएमटीएफ) द्वारा क्रमवार अभियान चलाकर की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने कार्रवाई को नियमित करने का निर्देश दिया।

साथ ही कहा कि कार्रवाई की जानकारी जिला खनन पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारियों को तत्काल दें। उन्होंने कोल उपक्रमों व कंपनियों को भी अपने स्तर से कोयला चोरी पर रोक लगाने को लेकर नियमित कार्रवाई करने को कहा।

सीओ से समन्वय बनाकर पुलिस करें कार्रवाई : एसपी

बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने अंचलाधिकारियों से समन्वय बनाकर सक्रिय रूप से अवैध खनन-परिवहन पर कार्रवाई करने का सभी एसडीपीओ व थाना प्रभारियों को निर्देश दिया। कहा कि छापेमारी एवं कार्रवाई का पूरा डाक्यूमेंटेशन करें, क्या और कब सूचना मिली, क्या कार्रवाई की गई, क्या मिला या नहीं मिला आदि की विस्तृत जानकारी थानों में संधारित करें और उसकी रिपोर्ट जिला को अगले दिन समर्पित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सीसीएल को वैध माइनिंग चालान के माध्यम से ही कोल रैक डिस्पैच करने को सुनिश्चित करने को कहा।

विभाग ने जिले में छह बालू घाटों से उठाव की दी अनुमति

जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार सिंह ने समिति को बताया कि जिले के कैटेगरी वन के छह बालू घाटों से बालू उठाव को लेकर विभाग से अनुमति प्राप्त हुई है। इसका संचालन संबंधित क्षेत्र के पंचायत कार्यालय द्वारा मुखिया या पंचायत सचिव आदि के माध्यम से होगा। इन घाटों के बालू का इस्तेमाल वाणिज्यिक कार्य के लिए नहीं होगा। इसका इस्तेमाल संबंधित पंचायत के ग्रामीण निजी कार्यों एवं विभिन्न सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ एक जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित कर बालू घाटों के संचालन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए संचालन शुरू कराने को कहा। वहीं, कैटेगरी टू बालू घाट, जिनका संचालन जेएसएमडीसी के माध्यम से होना है,उसकी निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। बैठक में मुख्यालय डीएसपी मुकेश कुमार, सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार, बेरमो एसडीपीओ सतीश चंद्र झा, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानों के थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक, विभिन्न कोयला कंपनियों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

झुलसाती तपिश में आंगनबाड़ी केंद्र से घर आना-जाना कर रहे नौनिहाल, बंद करने की मांग

संवाददाता

बोकारो थर्मल : बोकारो जिला सहित पूरे प्रदेश में मई माह के आरंभ से ही पड़ रही भीषण गर्मी से आम जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। दूसरी ओर आंगनबाड़ी केंद्र के नौनिहाल तपती धूप एवं भीषण गर्मी के बीच आंगनबाड़ी केंद्र से अपने घर तपती धूप में जाने को मजबूर हैं। तेज धूप एवं उमस भरी गर्मी के कारण सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक चौक-चौराहों पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया रहता है। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों से दोपहर बारह बजे छुट्टी के बाद पैदल आने जाने वाले बच्चे गर्मी से काफी परेशान दिखते हैं। गर्मी व तेज धूप के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से अभिभावक भी चिंतित हैं। गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों का समय 7 बजे से 11 बजे निर्धारित कर रखा है। केंद्र में 11 बजे छुट्टी के बाद मिड-डे मील खाकर घर लौटने के क्रम में बच्चों को 12 बज ही जाता है। तेज धूप एवं उमस भरी गर्मी के कारण छोटे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र जाने मे मुकरने लगे हैं। गर्मी के कारण कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों मे बच्चों की उपस्थिति भी कम होने लगी है। गर्मी को देखते हुए अभिभावकों ने तत्काल आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने की मांग की है।

मांग झारखंड आंदोलनकारियों ने गवई डैम का पानी सिंचाई तक नहीं पर पहुंचने पर जताई नाराजगी

सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों को राहत दिलाए सरकार : माहथा

संवाददाता

बोकारो : झारखंड आन्दोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बोकारो जिला प्रधान महासचिव राजदेव माहथा एवं जिला संयोजक हाबुलाल गोराई ने कहा कि झारखंड प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र चास-चंदनकियारी है। दोनों प्रखंड कृषि आधारित क्षेत्र है। इन दोनों प्रखंड के अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे रहकर गुजर-बसर करतें हैं। खेती पर ही निर्भर हैं। पिछले कई वर्षों सहित आए दिन वर्षा के अभाव में एवं मॉनसून के धोखा देने के कारण दोनों प्रखंड के किसान सुखाड़ के कारण जूझना पड़ता है। पिछले वर्ष 2022 को दोनों प्रखंडों के किसानों को प्राकृतिक आपदा से भारी सुखाड़ की स्थिति का सामना करना पड़ा था, लेकिन प्रदेश सरकार ने उदासीन रवैया अपनाया और किसानों को वर्तमान तक किसी भी तरह की राहत योजना नहीं चलाई। श्री माहथा व गोराई ने चंदनकियारी प्रखंड क्षेत्र के भ्रमण करने के दौरान कहा कि पिण्ड्राजोरा गवाई नदी डैम से निकला नहर चास-चंदनकियारी प्रखंड के सैकड़ों गांवों को होते हुए भोजूडीह तक जाता है। नेताद्वय ने चंदनकियारी प्रखंड के साबड़ा, सुतरीबेड़ा, जाराहारा, आंगदागोडा, बाबुडीह उद्गुटांड़, मायनटांड़, बड़ाजोर, माचाटांड़, मुराबदि, बोगुला, डुमरबाद, हड़ाय कुरवा, बारकामा, साहरजोरी, बोगुला, बरवाडीह, कोदुवाभीठा, लक्षनपुर, बांसगढ़ी, सिमुलिया, माढ़रा सहित दर्जनों गांवों के सामने निमार्णाधीन नहर का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि पिण्ड्राजोरा गवाई डेम का निर्माण कार्य 70 के दशक में आरंभ हुआ था, आज पांच दशक से ज्यादा हो गए, लेकिन वर्तमान तक पिण्ड्राजोरा से भोजूडीह तक हजारों किसानों के खेतों तक सिंचाई का जल नहीं पहुंच नहीं पाया। नहर द्वारा सिंचाई का जल खेतों के लिए किसानों को मिलता तो आज दोनों प्रखंडों के हजारों किसान-मजदूर खुशहाल होते। हमारे किसान-मजदूर भाइयों को सुखाड़ से जूझना नहीं पड़ता और न ही वे रोजी-रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों की ओर पलायन करते। यदि पूर्व जन-प्रतिनिधि एवं वर्तमान जन-प्रतिनिधि पिंड्राजोरा गवाई डैम एवं नहर के निर्माण में अति संवेदनशील होते तो पिण्ड्राजोरा से भोजूडीह तक हजारों किसानों के खेतों में हरियाली होती, लेकिन जन-प्रतिनिधियों में इच्छाशक्ति के अभाव में ही आज तक पांच दशक से किसान समस्याग्रस्त हैं।

हफ्ते की हलचल

स्वच्छता को ले डीवीसीकर्मियों ने निकाली प्रभातफेरी

चंद्रपुरा : दामोदर घाटी निगम, चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र प्रबंधन द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत डीवीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों एवं अन्य कर्मियों ने प्रभात फेरी निकालकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। डीवीसी प्लांट के मुख्य द्वार पर सुबह डीवीसी के कर्मचारी, अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित हुए और कतारबद्ध होकर डीवीसी अस्पताल तक पैदल मार्च किया। स्वच्छता को लेकर कर्मियों ने नारे लगाए। कार्यक्रम में डीवीसी के उप महाप्रबंधक (प्रशासन) टीटी दास, वरीय प्रबंधक दिलीप कुमार, प्रबंधक रविंद्र कुमार, अक्षय कुमार, अमूल्य सिंह सरदार, विनोद कुमार, अनिल कुमार गुप्ता, प्रदीप श्रीवास्तव, सत्येंद्र कुमार सिंह, राम कुमार दुबे, महेंद्र सिंह, अमरजीत कुमार सहित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान और स्थानीय लोग शामिल हुए।

सुखाड़ राहत योजना से किसानों को लाभ दिलाने पर चर्चा

गोमिया : गोमिया प्रखण्ड मुख्यालय के सभाकक्ष में अंचलाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो ने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक मुखिया, कृषक मित्र तथा राजस्व कर्मी के साथ की। उक्त लोगों को जानकारी देते हुए सीओ संदीप अनुराग टोपनो ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत जो श्रेणी (ख) के लाभुक किसान हैं तथा जिनके द्वारा श्रेणी (ख) में ऑनलाइन आवदेन दिया गया था, उन्हीं आवेदनों के सत्यापन के लिए तथा भुगतान के प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी जनप्रतिनिधि, कृषक मित्र तथा राजस्व कर्मी इस कार्य को सरलता से कैसे संपादित करें, इस संदर्भ मे विचार- विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सरकार के द्वारा घोषित राहत लाभुक किसानों को दिलवाने का प्रयास करेंगे। बैठक में मुखिया विनोद विश्वकर्मा, तेजलाल महतो, महादेव महतो, शर्मीला देवी, समाजसेवी उपेंद्र महतो, राजस्व कर्मी कैलाश यादव, जानकी कुशवाहा, कृषक मित्र सुनील पासवान, फूलचंद हेंब्रम, प्यारेलाल महतो, कामेश्वर महतो, भुनेश्वर रजवार, रामचन्द्र, कृष्णा प्रसाद, बालदेव महतो सहित कई अन्य लोग मौजूद थे।

पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व मंत्री राजेन्द्र सिंह

बेरमो : पूर्व मंत्री स्व. राजेंद्र प्रसाद सिंह की तृतीय पुण्यतिथि मनाई गई। ढोरी स्टाफ क्वार्टर स्थित बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह के आवासीय कार्यालय के समक्ष स्थापित स्व. सिंह की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों एवं ट्रेंड यूनियनों के पदाधिकारी तथा कार्यसमिति के सदस्यों और विपक्षी नेताओं के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा, पूजा-पाठ के बाद ब्राह्मण व दरिद्रनारायण भोज का भी आयोजन किया गया।

महिलाओं के लिए योग एवं ध्यान शिविर का आयोजन

बोकारो थर्मल : डीवीसी प्रबंधन की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा और हेल्दी लाइफस्टाइल के तहत डीवीसी के आफिसर्स क्लब में महिलाओं एवं युवतियों के लिए योग एवं मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि योगाचार्य वैद्य अनिल कुमार सिंह एवं विशिष्ट अतिथि डीवीसी के डीजीएम बीजी होलकर ने किया। शिविर को संबोधित करते हुए डीजीएम ने कहा कि योग विवेक और शांति प्रदान करता है, उनकी थकान से भर देने वाली दुनिया में साधारण श्वांस की तकनीक से महिलाओं को तनाव से मुक्ति मिलती है और वह बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरी दक्षता तथा शिष्टता से पूरा करती हैं। मौके पर उप निदेशक (एचआर) एए अशरफ, सहायक नियंत्रक (सीएसआर) सुनील कुमार, स्वाति होलकर, जीवाधन महतो, रमेश यादव, ओमप्रकाश यादव, महेीलाल मुर्मू, शिवचरण, एसएचजी ग्रुप की सावित्री महतो, महिला सिलाई प्रशिक्षक सुष्मिता बर्णवाल सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं युवतियां शामिल थीं। रविवार को प्लास्टिक बैन करने को लेकर जागरुकता अभियान चलाया जाएगा।

न्याय के नए मंदिर से न्याय का आह्वान

झारखंड में बना देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर, उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति ने सही न्याय-व्यवस्था पर दिया जोर

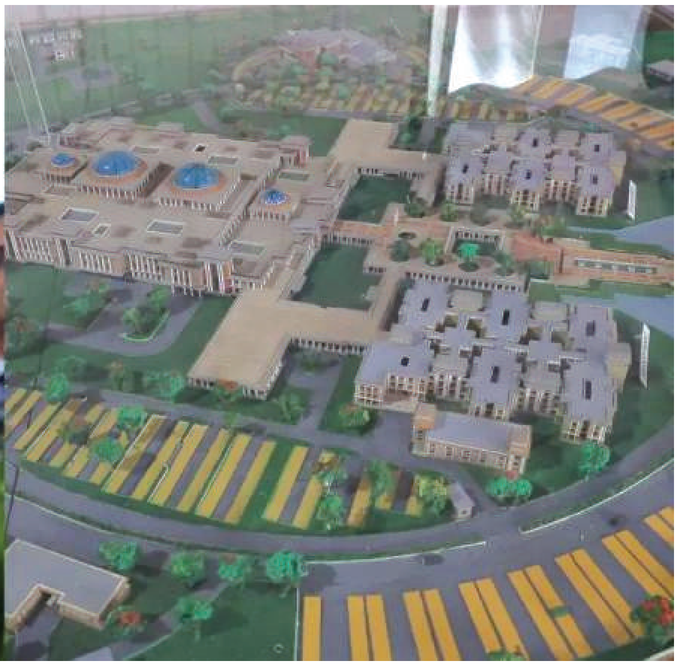

विशेष संवाददाता

रांची : अदालत यानी न्याय का मंदिर। झारखंड में नए हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन करते हुए देश की सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सच्चे न्याय का संदेश दे गईं। उन्होंने वर्तमान न्यायिक व्यवस्था पर कहीं न कहीं असंतोष जताया और रांची में नए न्याय के मंदिर से लोगों को सही मायने में न्याय दिलाने का आह्वान किया। महामहिम ने कहा कि सालों तक जो लोग न्याय का इंतजार करते हैं, उन्हें 10-15-20 साल बाद न्याय तो दे दिया जाता है, लेकिन न्याय उन्हें मिलता नहीं है। कई लोग मेरे पास आते हैं और यह कहते हैं कि मैडम न्याय तो हमें मिल गया है, लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमें न्याय का पालन करवाना है, जो नहीं हो रहा है। यह एक बड़ा विषय है और इस पर विचार करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर रांची में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने जब ये बातें कहीं, उस वक्त मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्र सहित न्यायपालिका से जुड़े बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए और अगर रास्ता नहीं है तो बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मंच से मैं बोल रही हूं, यहां भारत के मुख्य न्यायाधीश बैठे हुए हैं, यहां पर झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जस्टिस हैं, दूसरे न्यायालयों के न्यायविद् हैं। साथ ही भारत सरकार के कानून मंत्री भी हैं, एक बार इस विषय पर विचार करना होगा कि कई लोग कहते हैं कि न्याय नहीं अगर मिल रहा है तो कंटेंप्ट कर दो, लेकिन कंटेंप्ट केस करने के बाद भी हालात वही होंगे। 7 से 10 साल तक इंतजार करना होगा। आदेश फिर वही आएगा और न्याय नहीं मिलेगा, आखिर इसका इसका रास्ता क्या है? आप सभी लोग विचार करिए और साथ ही इसके लिए कोई रास्ता निकालिए। अगर कानून है तो उसका पालन करवाइए और अगर कानून नहीं है तो यह कानून बनना चाहिए।

हिन्दी बोलना भाषा की गरिमा : झारखंड में नए हाईकोर्ट भवन के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा - मैं इस बात का धन्यवाद देती हूं कि आज इस मंच से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हिंदी में अपना स्पीच दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं, जब इस तरह के मंच से हिंदी बोला जाएगा तो भाषा की गरिमा लोगों की समझ में आएगी और भाषा का विस्तार भी होगा। इस पर भी काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महिला हिंसा में जल्द न्याय की बात हो रही है, जो एक बेहतर कदम कहा जा सकता है, लेकिन इस बात पर भी विचार करना होगा कि जो क्षमता है, उससे कहीं ज्यादा लोग जेल में रखे गए हैं, जिस पर विचार करने की जरूरत है। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के बनने से निश्चित तौर पर न्याय व्यवस्था और झारखंड के लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी, इसके लिए झारखंड के लोगों को बधाई देती हूं। साथ ही, न्यायपालिका से अनुरोध करती हूं कि जो मामले जल्दी निपटाए जा सकते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन दिवसीय झारखंड दौरे पर थीं। उन्होंने देवघर पहुंच बाबा बैद्यनाथ धाम में विशेष पूजा-अर्चना की। इसके अलावा खूंटी में महिला स्वयंसहायता समूहों के साथ वार्तालाप भी की।

165 एकड़ में फैला है हाईकोर्ट, सुविधाएं अनेक

165 एकड़ में फैले इस हाईकोर्ट में सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। एंट्री गेट से ही इसकी भव्यता और खूबसूरती की झलक दिखने लगती है। कोर्ट बिल्डिंग के दोनों ओर भव्य बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें महाधिवक्ता के अलावा वकीलों के बैठने की जगह और लाइब्रेरी की व्यवस्था है। पूरे कोर्ट परिसर सेंट्रलाइज्ड एसी लगी हुई है।

न्याय में देरी भी अन्याय : राज्यपाल

नए हाईकोर्ट भवन के उद्घाटन के दौरान झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि नया हाईकोर्ट भवन लंबी सोच के साथ बना है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि हम भविष्य कैसे प्लान कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा, यह भवन सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बना, बल्कि यह लोकतंत्र का उदाहरण है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम सही समय पर फैसला दें, क्योंकि न्याय में देर करना भी अन्याय है। मुझे पूरा विश्वास है कि हाईकोर्ट के सभी जज और कर्मचारी राज्य के नागरिकों में लोकतंत्र और न्याय की व्यवस्था को और मजबूत करने में सहयोग करेंगे। मुझे संदेह नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की देख-रेख में झारखंड हाईकोर्ट बेहतर करेगा। हाईकोर्ट न्याय का मंदिर है जहां लोग इंसाफ के लिए पहुंचते हैं। यही वजह है कि हमारा लोकतंत्र लगातार मजबूत हो रहा है।

जिला न्यायालय को बराबरी देने की जरूरत : सीजेआई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के सात साल के मेरे निजी अनुभव में सजा होने से पहले गरीब लोग कई दिनों तक जेल में बंद रहते हैं। अगर न्याय जल्दी नहीं मिले, तो उनकी आस्था कैसे बनी रहेगी। जमानत के मामलों में प्रत्यक्ष रूप में हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिला न्यायालय को बराबरी देने की जरूरत है। जिला न्यायालय की गरिमा नागरिकों की गरिमा से जुड़ी है। न्याय प्रणाली का लक्ष्य सामान्य नागरिक को न्याय दिलाना है। मुकदमों की जानकारी मिले, समय पर सुनवाई हो, कागजात सही समय पर मिले। कैंटीन की व्यवस्था सही हो, महिलाओं के लिए शौचालय हो। हमें अपने आप से कठोर सवाल पूछने होंगे।

भारत और नेपाल मिलकर तस्करी के खिलाफ कसेंगे नकेल, बनाई रणनीति

सतीश कुमार झा

सीतामढ़ी : तस्करी के खिलाफ भारत और नेपाल, दोनों देश मिलकर अब पूरी संजीदगी के साथ नकेल कसेंगे। भारत-नेपाल सीमा संयुक्त समन्वय समिति ने मादक पदार्थों, मानव, हथियार और मुद्रा तस्करी के साथ-साथ सीमा संबंधी अन्य मुद्दों को लेकर ठोस रणनीति तैयार की है। समिति की बैठक समाहरणालय स्थित विमर्श सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सीतामढ़ी के जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी, कमांडेंट एसएसबी 51वीं एवं 20वीं बटालियन, एडीएम राजस्व, एएसपी सीतामढ़ी, नेपाल के महोत्तरी, सर्लाही एवं रौहतक जिले के सीडीओ, सहायक सीडीओ, एसपी सहित दोनों पक्षों के कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे। काफी सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की तस्करी पर पूरी सख्ती के साथ रोक लगाने पर व्यापक चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने अनुरोध किया कि सीमा से नेपाल क्षेत्र में कम से कम दी-तीन किलोमीटर शराब की दुकान शिफ्ट करें। इसके अतिरिक्त हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, दोनों देशों की मुद्रा की तस्करी एवं अन्य मादक पदार्थों की तस्करी पर पूरी सख्ती के साथ रोक लगाने एवं एक-दूसरे को सूचनाओं के आदान-प्रदान पर भी सहमति बनी। विशेषकर, बाढ़ के समय सूचनाओं के आदान-प्रदान पर बल दिया गया, ताकि प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बाढ़ के समय त्वरित कदम उठाया जा सके। बैठक में सीमा पर अतिक्रमण एवं सीमा स्तंभों की मरम्मत पर भी चर्चा की गई। तीसरे देशों के नागरिकों का अवैध तरीकों से भारत में प्रवेश नहीं करने को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई एवं ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने पर भी सहमति बनी। इसी क्रम में बिहार के रास्ते भारत में नेपाल से फेक करेंसी के आवागमन पर रोक लगाने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही, सीतामढ़ी के सुरसंड में आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर दोनों देश के बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर सहमति बनी। बॉर्डर एरिया में रात्रि गश्ती पर बल देने की बात कही गई। साथ ही, अनुरोध किया गया कि नेपाल से नदी के रास्ते आने वाले अपराधियों पर नकेल कसी जाय। लोकल बॉर्डर पुलिस आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए दोनों ही तरफ के अपराधियों पर नकेल कसें। दोनों देशों में एक-दूसरे के अपराधियों की सूची एवं उनसे संबंधित जानकारी को एक-दूसरे से साझा करने पर सहमति बनी। बैठक के अंत में दोनों देशों के अधिकारियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।

वर्षों से नाले में तब्दील है खड़का की लाइफ-लाइन सड़क

खड़का : खड़का पंचायत की सड़कों में लाइफलाइन मानी जाने वाली बजरंगबली मंदिर से दुर्गा मंदिर तक की सड़क विगत लगभग एक दशक से नाले में तब्दील है। मामूली बारिश होने पर यह सड़क पैदल चलने के लायक भी नहीं रह जाती। ग्रामीणों का कहना है कि खड़का पंचायत में रोड की समस्या बहुत बड़ी है। पंचायत इस मामले में दयनीय स्थिति में है। इस ओर पंचायत प्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। पंचायत प्रतिनिधि के उदासीन एवं अक्षम रवैए से जनता परेशान है। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक पर भी खड़का की उपेक्षा का आरोप लगाया है। कहा कि चुनाव से पहले जितना कुछ बोला गया, वो सब हवा-हवाई में ही रह गया। इधर, कुछ लोगों का कहना है कि पंचायत में जितना फंड आता है, उसी के हिसाब से काम होता है। सबसे कम फंड इसी पंचायत में आता है। उसमें इस सड़क को बनवा पाना संभव नहीं। केवल साइड से एक नाला ही निकाला जा सकता है। मुखिया बगैर एनओसी के इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। कुल मिलाकर सिस्टम के झोल में सड़क की समस्या जस की तस बनी है और लोग परेशान हैं।

मिथिला डायरी

कामनाओं के कारण ही संसार क्रियाशील

गुरुदेव श्री नंदकिशोर श्रीमाली

ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति निष्ठा और भक्ति के मार्ग पर ही सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कामना पूर्ति का अर्थ है- सफलता और कामना पूर्ति के लिए चाहिए शक्ति, ...और शक्ति तो भक्ति से ही मिलती है। सिर्फ भक्ति ही प्रेम भावनाओं से ओत-प्रोत है। नर और नारायण के बीच भेद मिटाने का रास्ता भक्ति ही है।

नारायण 'भावजल' में विराजमान हैं और मनुष्य भावना के सागर में गोते लगाता रहता है। भावना का यह संसार बड़ा ही उलझा हुआ है, जटिल है। यहां पर सही और गलत कई बार समझ में नहीं आता है। भावनाएं ऐसी ही होती हैं। एक बात स्मरणीय है, जैसे मोह विवेक से शुद्ध होता है, वैसे ही भावनाएं भक्ति से शुद्ध होती हैं। जब प्रेम निष्ठा से जुगरता है, श्रद्धा में परिपक्व होकर भक्ति रस में बदल जाता है तो फिर दुनिया ही बदल जाती है। सब ओर रस ही रस आता है। तब यह सारा जगत कल्पतरु बन जाता है, क्योंकि भक्ति के पास अपूर्व शक्ति है। उसके सामने सब नतमस्तक है। भक्त गागर में सागर भर सकता है, क्योंकि भक्त से ही तो भगवान हैं और इस भक्ति-रस में रंगने का पाठ्यक्रम गुरु ही चलाते हैं, गुरु की पाठशाला में। गुरु की यह पाठशाला और गुरु का यह पाठ बहुत श्रेष्ठ है। बस, इस पर वही शिष्य चलते हैं, जो अपना शीष गंवाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। उनकी गुरु में अटूट निष्ठा है। जहां ऐसी श्रद्धा है, वहां कुछ भी संभव है। हर समय भरोसा रखो, गुरु की सत्ता पर और याग रखो कि गुरु तुम्हारा सहयोगी है। तुम्हारे जीवन में अमृत प्रवाह, रस प्रवाह के लिए ही गुरु है।

समस्या इतनी ही है कि लोग गुरु को तौलते-मोलते बहुत हैं। न तो गुरु को तौलना है, न गुरु को परखना है। अरे भाई! गुरु और शिष्य का सम्बन्ध प्रेम है, एक जुड़ाव है, जिसे संसार की कोई भी शक्ति तोड़ ही नहीं सकती। जुड़े हैं हैं ते हम भावों से, मन से, आत्मा से।

84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य शरीर मिला है और तुम इसे गंवा रहे हो? बिना ऊंची क्लास में गये अपने जीवन को कैसे बदल सकते हो? आपके गुरु चाहते हैं कि कामनाओं से ऊपर उठो और यह भी बात है कि कामनाएं पूर्ण होने के बाद ही कामनाओं से ऊपर उठ सकते हैं। एकदम सरल बात है। कामना के कारण ही यह संसार क्रियाशील है।

ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका
क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते

देखो! कामना बीज है और इस बीज से ही हर व्यक्ति अपने जीवन को बड़ा बनाता है, भव्य बनाता है। कामना मनुष्य को बड़ा बनने के लिए प्रेरणा देने वाली, उत्साह देने वाली शक्ति है और गुरु वह कल्पतरु है, जहां जिसकी छांव में, जिसके सानिध्य में हर कामना सफल होती है। क्योंकि, कामना बीज है और बीज तो उगेगा ही उगेगा।

अब जैसे ही कामना मन में आती है, उपद्रव होता है, जोरदार उपद्रव। ठीक वैसे ही, जैसे जमीन को फोड़कर बीज अंकुरित होता है। यह उपद्रव है क्रिया और इस उपद्रव का एक नाम है- विचार। यह उपद्रव मन में उथल-पुथल कर देता है, जबकि आगे बढ़ने का नाम ही तो कामना है।

एक बात विचार योग्य है कि कामनाओं के देव को, कामदेव को मन्मथ कहते हैं, क्योंकि जहां कामना है, वहां मंथन भी है, जहां कामना है, वहां संघर्ष है, जहां कामना है, वहां प्रपंच है और जहां कामना है, वहां अमृत है। तो सत्य यह है कि विष और अमृत दोनों ही कामना के ज्वार में फूटते रहते हैं। इसलिए पुराणों में बार-बार अमृत मंथन की बात आई है।

वास्तव में क्या है अमृत मंथन? देवताओं और उनके भाइयों के बीच चाहे धन कहो, चाहे कामना कहो, उसके लिए बंटवारे का संघर्ष ही है। आप एक क्षण के लिए अपना नजरिया बदल कर देखें तो कौन सुर है, कौन असूर है, इसकी परिभाषा तय करना कठिन हो जाएगा। एक विशेष बात है, कामनाओं को पूरा करना ठीक वैसे ही, जैसे एक तपते हुए गर्म तवे पर जल के छींटे डालने जैसा है।

मन में पनपने वाला शुभ विचार है कामना

जब तक हम कामनाओं को पूरा करते जाएंगे, तब भी आ-राम नहीं मिलेगा। क्योंकि, फिर एक नई कामना उत्पन्न होगी। क्योंकि, कामना का अर्थ है क्रियाशीलता और जिसमें कामना समाप्त हो गई, वह निष्क्रिय हो जाता है। पर एक बात है, यदि हम अपनी कामनाओं पर संतोष का मलहम, लेप लगा दें तो हम कामना से परे जाने की विद्या सीख जाते हैं।

हमारे जीवन में एक अद्भुत बात है। अब मनुष्य जीवन में जो विचार हैं, वह अनुभव बनते हैं। अब तक जो जीवन हमने जीया, हमारा भूतकाल, हमारे आज के अनुभव, अनुभूति को निर्धारित करता है। किसी व्यक्ति से हमारी बिल्कुल नहीं बनती है, किसी व्यक्ति से या नई जगह को देखकर एकदम जाना-पहचाना, अपनापन लगने लगता है। ठीक ऐसे ही हम विचार करें कि वर्तमान समय के पार भूतकाल में क्या स्थिति थी, क्या संबंध था? जैसे भूतकाल की घटनाओं के आधार पर वर्तमान को जोड़ते हैं, उसी प्रकार हमारी कामनाएं हमारे वर्तमान को भविष्य से जोड़ती हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं 'Will' अर्थात इच्छा, मन की चाहत और भविष्य में होने वाले क्रियाकलाप, ऐसा होगा।

तो 'Will' क्या है? भविष्य का स्वरूप। यही हमारी इच्छा को दर्शाता है। ऐसे ही एक शब्द है-'Can', कर सकता हूं। 'I Can Do it'. यह तो हमारी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए है। यह कर सकता हूं वर्तमान काल में स्थित है और भविष्य के लिए आने वाले कल के लिए- मैं एवरेस्ट पर चढ़ूंगा। 'I Will Win'. तो 'Will' क्या है? भविष्य में अपने कार्य फलीभूत करने के लिए एक विचार है और यह विचार हमारे मन में उठ रही कामना की तरंग है। तरंग तो उठनी ही चाहिए। जीवन में तरंग उठेगी, तब ही तो क्रिया होगी। इसलिए कामनाओं को गलत मत समझो, कामना तो मन में पनपने वाला एक शुभ विचार है।

तो जब 'Will' में, कामना में अपनी इच्छाशक्ति का सहयोग हो जाता है तो बन जाता है- 'Willpower'. 'Willpower' क्या है? इच्छा और शक्ति का मिलन, जो आज नहीं है, वह भविष्य में प्राप्त हो, यही इच्छा तो 'Willpower'है, यही कामना है।

उपनिषद में कहा गया है- हे मनुष्य! तुम उत्तम लोक की इच्छा करो, तुम्हें उत्तम लोक अवश्य प्राप्त होंगे। अब देखो! आप साधक हो, शिष्य हो, किन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप प्रयासरत हैं, यह आपके व्यक्तित्व का स्पष्ट आईना है। कितना उत्साह है आपके अंदर चुनौती स्वीकार करने की, कितनी योग्यता है, इसे आप नापना चाहते हो तो वह आपकी कामना है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अपने जीवन में कामनाओं को नकारो मत, निराशावादी मत बनो।

कोई मनुष्य हो और कामनाएं नहीं हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। मनुष्य इस पृथ्वी लोक में कामनाओं के कारण ही आता है और जो व्यक्ति इस लोक में आप्तकाम हो जाता है, जो अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है, वह पुनः इस लोक में नहीं आता है। वह अपने जीवन पूर्ण होने पर पूर्ण मदः पूर्ण मिदं... होकर ब्रह्मलोक में आनंदमय हो जाता है।

वेद वाक्य है- जो इस पृथ्वी पर आया है, उसके मन में इच्छा का अंकुर अवश्य है। कुछ रह गया है पिछले जन्म का, जिसे पूरा करने इस जन्म में पुनः आया है। इसलिए कामनाओं को मत नकारो। जब कामना अधूरी रह जाती है तो मन टूटता है और मन टूटता है तो शरीर तो व्यथित होगा ही, दुःखी होगा ही।

रक्तबीज और महिषासुर की तरह हैं कामनाएं

देखो! कामनाओं के संसार में आप जीत भी गए, कामनाएं बढ़ाते गए, उनकी पूर्ति करते गए तो भी मात खा जाओगे। क्योंकि, कामनाएं तो बहुरूपिया हैं, महिषासुर की तरह हैं, रक्तबीज की तरह हैं, अनेक रूप हैं, ऐसे ही कामनाओं के अनेक रूप हैं। एक पूरा करोगे, दूसरी मिलेगी। कामना तो आपकी परछाई है, उससे लड़ रहे हो। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी।

अरे भाई! सीधी-सादी बात है। कामना मोह का ही तो स्वरूप है। पर मैं स्पष्ट कहता हूं कि वह खराब नहीं है। मोह का अंकुर कामना से ही जन्मता है। जब तक मोह का अंकुर नहीं होगा, इच्छा उदित नहीं होती है। जब इच्छा उदित नहीं होती है तो शिव शांत रहते हैं, विष्णु क्षीरसागर में शयन करते हैं और ब्रह्मा तप करते हैं। सृष्टि निःस्पंद रहती है।

यह सब आध्यात्मिक बातें नहीं हैं। हर व्यक्ति के जीवन में देख लीजिए। जब तक जीवन में खर्च शुरू नहीं होता है, कमाने की इच्छा नहीं होती। अगर आप निरंतर-निरंतर कामनाओं का रक्तबीज बढ़ाते जाओगे, फिर संतोष समाप्त हो जाएगा। आपको हर बार यही लगेगा कि कुछ अधूरा है। जो कर रहे हो, वह पूर्ण हो और स्वयं के साथ ईश्वर को भी स्वीकार्य हो। जो आपके पास है, इसे स्वीकार करो, बस आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश उदित हो जाएगा। कर्म करेंगे, लेकिन संतोष के साथ, आनंद के साथ। इस सत्य को स्वीकार कर लो, आपकी कामनाएं जो पूर्ण हुई हैं और हो रही हैं, वह आपकी पूजी हैं। इसे सुरक्षित रखो, जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी, खुशी आ जाएगी।

(साभार : निखिल मंत्र विज्ञान)

फेफड़े और हृदय को नुकसान पहुंचाता है खड़े होकर पानी पीना

बुजुर्गों को हमने अक्सर यह कहते सुना है कि खड़े होकर पानी न पिएं। इसके पीछे बड़ा कारण है। एक रिसर्च के मुताबिक खड़े होकर पानी पीने से हमारे शरीर को सही तरह से न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व.नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि इस तरह पानी पीने से, पानी मुंह से होते हुए बहुत तेजी से नीचे चला जाता है। जिससे लंग्स और हार्ट को भी नुकसान पहुंचता है। साथ ही इससे फूड और विंड पाइप में होने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। ऐसा करने से हेल्थ रिलेटेड कई परेशानियों को फेस करना पड़ सकता है। दरअसल, जब खड़े होकर पानी पीते हैं तो इसका डायरेक्ट असर हमारे नवर्स सिस्टम पर पड़ता है। इस तरह से पानी पीने से न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं और शरीर टेंशन की पोजिशन में आ जाता है।

बढ़ती उम्र के साथ दिखता है असर

आयुर्वेद के अनुसार, इसका असर तुरंत नहीं दिखाई देता है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे-वैसे शरीर में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इससे पानी तेज स्पीड से फूड पाइप से होते हुए सीधे पेट के निचले हिस्से पर पहुंच जाता है। इससे आस-पास की लेयर्स में एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है, जो खतरनाक होता है। इससे लिक्विड सबस्टेंस का बैलेंस बिगड़ जाता है। पेट दर्द और बदहजमी की शिकायत हो जाती है।

किडनी के लिए खतरनाक - जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं, तो पानी बिना फिल्टर हुए निचले पेट की तरफ तेजी से बढ़ता है। यह पानी में जमा इंप्योरिटीज को ले जाकर गॉलब्लैडर में जमा कर देता है, जो किडनी के लिए डेंजरस हो सकता है। इससे यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती हैं।

कमजोर हड्डी व दर्द - खड़े होकर पानी पीने की वजह से जोड़ वाले हिस्से में लिक्विड सबस्टेंस की कमी होने से दर्द के साथ कमजोरी आने लगती हैं। हड्डियां कमजोर होने के चलते गठिया या घुटने खराब होने जैसी बीमारी होने लगती है।

इसी वजह से कई बार एकदम से पानी पीने पर सीने में तेज चुभन वाला दर्द होने लगता है।

बैठकर पीने के फायदे

जानकारों के अनुसार पानी पीने का सही तरीका है बैठकर पीना। कुर्सी पर बैठें, पीठ को सीधा रखकर रिलैक्स होकर ही पानी पिएं। बैठकर पीने से ये शरीर के सभी हिस्सों तक अच्छे से पहुंचता है। शरीर को पानी की जितनी जरूरत होती है, उतना पानी शरीर अच्छे से अवशोषित कर लेता है। बाकी हार्मफुल सबस्टेंस यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। ऐसे पानी पीने से खून में हार्मफुल सबस्टेंस नहीं घुलते और खून साफ रहता है। बैठकर धीरे-धीरे पानी पीने से इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस अच्छा बना रहता है और शरीर को जरूरी मिनरल्स मिलते रहते हैं। न्यूट्रिएंट्स दिमाग तक पहुंचते हैं और ब्रेन एक्टिविटी में सुधार आता है। पाचन दुरुस्त होता है पेट में सूजन या पेट फूलने की दिक्कत नहीं होती है।

डिजिटल इंडिया का उदय : प्रौद्योगिकी से राष्ट्र का परिवर्तन

राजेश कुमार सिंह
सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

21वीं सदी में सतत आर्थिक विकास तेज गति से तकनीकी प्रगति से प्रेरित है, जिसने हमारे जीने, काम करने और बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी है। डिजिटलीकरण की दिशा में सरकार ओर से जोर दिए जाने और प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने से हाल के वर्षों में भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। 1.4 बिलियन से अधिक लोगों वाला भारत देश विश्व स्तर पर इंटरनेट का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। भारत में 800 मिलियन से अधिक इंटरनेट कनेक्शन हैं और प्रति ग्राहक औसत मासिक डेटा खपत 16 जीबी से अधिक है, जो 2014 के बाद से 266 गुना की चौंकाने वाली वृद्धि है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) परियोजना जैसी पहलों के साथ हाल के वर्षों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए भारत सरकार के प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा, सरकार ने भारत में डेटा केंद्रों के विकास को सुविधाजनक बनाने और एक मजबूत दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन और राष्ट्रीय डेटा केंद्र नीति भी शुरू की है। इनके परिणामस्वरूप, व्यवसायों और लोगों को तेज इंटरनेट गति, बेहतर नेटवर्क कवरेज और डिजिटल सेवाओं तक बेहतर पहुंच का लाभ मिल सकता है।

अपने दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए, भारत ने एक विश्वस्तरीय डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इंडिया स्टैक भारत में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एक कलेक्शन से जुड़ा है। यह तीन अलग-अलग लेयर्स- विशिष्ट पहचान (आधार), पूरक भुगतान प्रणाली (एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), आधार भुगतान ब्रिज, आधार समर्थित भुगतान सेवा) और डेटा एक्सचेंज (डिजिलॉकर और खाता एग्रीगेटर) से बना है। ये सार्वजनिक और निजी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए ऑनलाइन, पेपरलेस, कैशलेस और गोपनीयता-संरक्षित डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

जन धन, आधार और मोबाइल की तिकड़ी यानी जेएएम ट्रिनिटी - भारत के परिवर्तित डिजिटल भुगतान परिदृश्य के केंद्र में एक महत्वपूर्ण संबल है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। इसे अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य बैंकिंग सेवा से वंचित हरेक परिवार को व्यापक तौर पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। जन धन खाते, आधार और मोबाइल कनेक्शन इन सभी ने डिजिटल इंडिया की स्थापना में योगदान दिया है। इसके अलावा, अनेक प्लेटफार्मों में ऑनलाइन शिक्षा, ई-मेडिसिन, फिनटेक, बेहतर कृषि पद्धतियां, अंतिम व्यक्ति तक निर्बाध सेवा का वितरण सुनिश्चित करने जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा प्लेटफार्मों का लाभ उठाया गया है। कोविन और डिजिटल सर्टिफिकेट जैसी ऑनलाइन प्रणालियों को आज दुनिया भर में सफलता की कहानियों के रूप में उद्धृत किया जा रहा है।

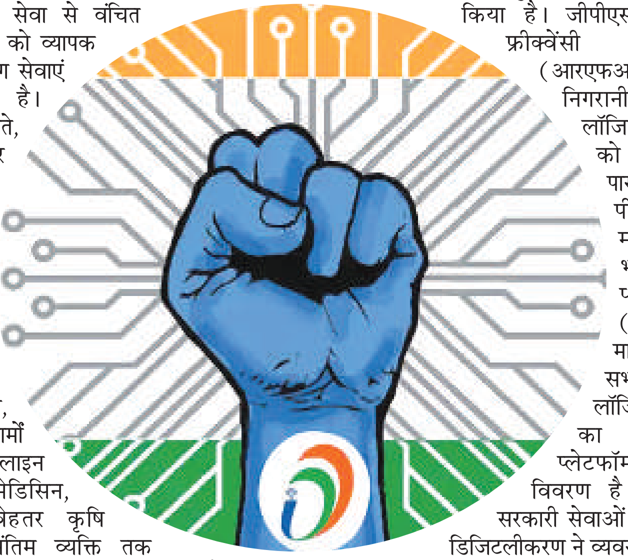

यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) की डिजिटल क्षमता से उद्योग जगत से जुड़ी हस्तियों को भी जबरदस्त फायदा हुआ है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी लाना और देश में औसत लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी शुरूआती बाधाओं को दूर करने और व्यापक बाजारों तक पहुंच के लिए अग्रणी है। यह ई-कॉमर्स क्षेत्र में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के रूप में दिखाई दे रहा है जो एमएसएमई के लिए उभरते अवसरों का लाभ उठाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

सामान की तेज और कुशल आवाजाही को सक्षम करने के लिए, सरकार ने देश के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए अत्यधिक निवेश किया है। जीपीएस ट्रैकिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) और तत्क्षण निगरानी की सुविधा ने लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस को और अधिक पारदर्शी बना दिया है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्र पर देश में सभी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक सुविधाओं का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मानचित्रण का विवरण है। इसके अलावा, सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण ने व्यवसायों के लिए नियमों के अनुपालन में लगने वाले समय और पहलों को कम कर दिया है, जिससे निवेशकों के लिए भारत में अपना व्यवसाय स्थापित करना और संचालित करना आसान हो गया है।

नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) भारत सरकार की एक पहल है, जो व्यापारियों को एक ही पोर्टल के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेजों और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने की अनुमति देकर व्यवसायों के लिए सरकारी अनुमोदन को कारगर बनाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करती है, जिससे कई एजेंसियों के लिए भाग-दौड़ करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तथा मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाले समय के साथ-साथ लागत भी कम हो गई है। एक और उदाहरण जो खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार के प्रयासों को प्रदर्शित करता है, वह है गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम), जो एक ऑनलाइन खरीद प्लेटफार्म है जिसे खरीद संबंधी गतिविधियों के लिए खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक समावेशी, कुशल और पारदर्शी, एक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी प्लेटफार्म बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।

स्टार्टअप इंडिया पहल भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना है। माननीय प्रधानमंत्री ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया था। भारत का फलता-फूलता स्टार्टअप इकोसिस्टम देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रमाण है, जिसने उद्यमियों को वे उपकरण और संसाधन प्रदान किए हैं जिनकी उन्हें पारंपरिक व्यापार मॉडल के स्थान पर नए मॉडल को अपनाने में आवश्यकता है। पिछले पांच वर्षों में, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त 92,683 से अधिक स्टार्टअप के साथ, भारत का स्टार्टअप परिदृश्य दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हो गया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के लिए एक समर्पित पोर्टल भी स्थापित किया है और पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को कारगर बनाने के उपाय किए हैं।

उपभोक्ताओं और पर्यावरण की बदलती जरूरतों के साथ आर्थिक प्रक्रियाएं लगातार विकसित हो रही हैं। निकट भविष्य में, उभरती भविष्य की प्रौद्योगिकियां लगभग सभी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का एक अनिवार्य तत्व होंगी। हमारे सामने चुनौती इन प्रक्रियाओं को और अधिक समावेशी और मानवीय बनाने की है, ताकि सामान्य व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंच सके।

भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 'कारोबारी सुगमता के शीर्ष पर जीवन सुगमता' को बढ़ावा देने के प्रयास में जुटा है, क्योंकि इसका उद्देश्य व्यवसायों और नागरिकों दोनों को लाभान्वित करने के लिए एक समावेशी और लोकतांत्रिक परिदृश्य को बढ़ावा देना है।

बोकारो स्टील में 5-एस सिस्टम ऑफ वर्कप्लेस मैनेजमेंट प्रतियोगिता के विजेता हुए सम्मानित

संवाददाता

बोकारो : 24-25 मई को बीएसएल के सीओ एवं सीसी विभाग के एचआरडी हाल में क्यूसीएफआई, बोकारो चैप्टर द्वारा आयोजित 5-एस सिस्टम ऑफ वर्कप्लेस मैनेजमेंट प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक (एमआरडी) आर. धवन, मुख्य महाप्रबंधक (सीओ एवं सीसी) राकेश कुमार, महाप्रबंधक (एसआरयू) सह सचिव क्यूसीएफआई, बोकारो चैप्टर एमके दुबे, महाप्रबंधक (नगर सेवाएं) राजुल हर्करनी सहित विभिन्न विभागों के विजेता प्रतिभागी उपस्थित थे। कार्यक्रम के आरम्भ में एमके दुबे ने सभी का स्वागत किया तथा 5-एस सिस्टम ऑफ वर्कप्लेस मैनेजमेंट के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। श्री आर धवन ने 5-एस सिस्टम ऑफ वर्कप्लेस मैनेजमेंट की महत्ता को रेखांकित करते हुए 5-एस को संयंत्र के साथ-साथ घर में भी कार्यान्वित करने का संदेश दिया।

अपने संबोधन में राकेश कुमार ने कहा कि 5-एस सिस्टम ऑफ वर्कप्लेस मैनेजमेंट को कार्यस्थल पर कार्यान्वित करने से सुरक्षित कार्यशैली विकसित होती है। तीन सत्रों में आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 28 समूहों ने अपने अपने कार्यस्थलों पर क्रियान्वयित किये गए 5-एस सिस्टम ऑफ वर्कप्लेस मैनेजमेंट को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से निर्णायक मंडली के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रस्तुतीकरण के दौरान निर्णायक मंडली के सदस्य के रूप में सहायक महाप्रबंधक (बीपीएससीएल) संजय सिन्हा, सहायक महाप्रबंधक (सिंटर प्लांट) आरके बेहरा, वरीय प्रबंधक (सीआरएम) एनसी पाठक, वरीय प्रबंधक (सेफ्टी) आरपी गुप्ता, सहायक प्रबंधक (सेफ्टी) एस सुमन, विजिलेंस इंस्पेक्टर (एसआरयू) अमन कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि द्वारा प्रतियोगिता के विजेताओं को गोल्ड एवं सिल्वर अवार्ड देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक (सीओ एवं सीसी) लखविंदर सिंह ने तथा धन्यवाद ज्ञापन महाप्रबंधक (नगर सेवाएं) राजुल हर्करनी ने किया।

चल जंगल चल

चल जंगल चल, चल जंगल चल
जंगल में हैं कीट-पतंग
अनिवार्य वन के ये अंग
चकित करे इन सबका काम
ढोते जीवन का पैगाम
ये मिलकर के संग हवा के
करें परागण, जंगल में अभिसार...जंगल
चल जंगल चल, चल जंगल चल

चल जंगल चल, चल जंगल चल
जंगल में ना-ना फल बनते
उनसे ही फिर बीज निकलते
बीजों को फैलाता जंगल
नव-नव पौध बनाता जंगल
इस क्रम से जंगल बढ़ता है
करता अपना नित नवीन विस्तार... जंगल
चल जंगल चल, चल जंगल चल

(क्रमशः)

कुमार मनीष अरविन्द

पेज- एक का शेष

बेलगाम माफियागिरी...

सीसीटीवी फुटेज की जांच कराकर असली दोषियों को सजा दी जाय। ऐसा नहीं होने पर सेंगेल आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उन्होंने राज्य के हेमंत सरकार पर आदिवासियों के हितों की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया। कहा कि झामुमो सोरेन सरकार में भू-माफियाओं को बढ़ावा मिल रहा है। समाजसेवी सुरेश मुर्मू की बर्बरतापूर्ण हत्या के पीछे राजनीतिक वोट बैंक से जुड़े अन्याय, अत्याचार और शोषण का मामला है। कहा कि झामुमो सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, तो दूसरी तरफ राजनीति के लिए संताल परगना को बर्बादी कगार पर पहुंचा दिया गया है। इसका खामियाजा असली सरना आदिवासियों को रोज भुगतान पड़ रहा है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वत्वाधिकारी विजय कुमार झा द्वारा डीबी कॉर्प लिमिटेड, भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, गोविन्दपुर रोड, जीके आश्रम, धनबाद से मुद्रित एवं सेक्टर-3बी/94, बोकारो स्टील सिटी (झारखंड) से प्रकाशित। **संपादक : विजय कुमार झा***
प्रबंध संपादक : **कंचन झा**, दिल्ली ब्यूरो : **श्रवण कुमार झा,** फोन/फैक्स : (06542) 246899, E-mail : mithilavarnan@gmail.com, आरएनआई. पंजीयन संख्या : 48973/89 (*पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये जिम्मेवार)

लोकतंत्र का नया मंदिर- नव भारत, नव अभ्युदय

नई धरोहर... संस्कृति, कला, शिल्प और वास्तु की विविधता का समृद्ध स्वरूप है नया संसद भवन

ब्यूरो संवाददाता

नई दिल्ली : लोकतंत्र भारत की अमूल्य निधि और वैश्विक पहचान है। नए संसद भवन के रूप में देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिला है, जो कई मायनों में नए भारत में नव अभ्युदय का द्योतक बनेगा। विदित हो कि दिल्ली कई सदियों से सत्ता का प्रमुख केन्द्र रही है। ब्रिटिश सत्ता ने प्रारम्भ में अपनी राजधानी कलकत्ता में स्थापित की थी और बाद में दिल्ली। तत्कालीन शासक किंग जॉर्ज प्रथम ने 12 दिसंबर 1911 में इसकी आधारशिला रखी थी। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और अलबर्ट बेकर ने इस नए नगर की योजना बनाई थी। लगभग बीस वर्ष बाद योजना पूरी हुई। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। नए भवन की अनेक विशिष्टताएं हैं। नवनिर्मित संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास 'सेंगोल' की स्थापना की गई है। यह पांच फीट लंबा चांदी से बना दण्ड है। इस पर सोने की पॉलिश है।

चोल साम्राज्य की प्राचीन परंपरा से जुड़ाव

आठवीं सदी के बाद से लगभग आठ सौ वर्ष तक चोल साम्राज्य था। चोल साम्राज्य में सत्ता का हस्तांतरण इसी 'सेंगोल' से होता था। विद्वान राजनेता सी. राजगोपालाचारी के सुझाव पर तमिलनाडु के तिरुवदुथुराई मठ ने इसे तैयार कराया था। इसके शीर्ष पर न्याय के रक्षक और प्रतीक नंदी अटल दृष्टि के साथ मौजूद हैं। चोल शिव उपासक थे। सेंगोल तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से निकला है। इसका अर्थ धर्म निष्ठा और सच्चाई होता है। सेंगोल राजदण्ड भारतीय शासक की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। 14 अगस्त 1947 को पं. जवाहर लाल नेहरू ने तमिलनाडु की जनता से सेंगोल को स्वीकार किया था। ब्रिटिशों से सत्ता हस्तांतरण के लिए राजाजी ने चोल वंश के सत्ता हस्तांतरण से प्रेरणा लेने का सुझाव दिया। चोल वंश में एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता सौंपते समय पुजारियों का आशीर्वाद लिया जाता था। सेंगोल का प्रतीकात्मक हस्तांतरण भी होता था। चोल राजवंश वास्तुकला और संस्कृति के संरक्षण में असाधारण योगदान के लिए प्रसिद्ध था। सी. राजगोपालाचारी के सुझाव के बाद तमिलनाडु के तिरुवदुथुराई मठ ने सेंगोल तैयार कराया था। पूरा भारत नए संसद भवन की खूबसूरती के साथ चोल साम्राज्य की प्राचीन परंपरा से भी जुड़ रहा है। 10 दिसम्बर 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारतीय संसद की नई इमारत का शिलान्यास किया गया था, जिसे ढ़ाई वर्ष से भी कम समय में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा कर लिया गया है और अब 28 मई को इसके उद्घाटन के साथ ही संसद का पुराना भवन प्राचीन धरोहर का हिस्सा बन जाएगा।

जानिए... नए संसद भवन की जरूरत क्यों

बहरहाल, राजनीतिक खींचतान अपनी जगह, लेकिन जहां तक इस सवाल की बात है कि ब्रिटिश काल में बने पुराने भव्य और मजबूत संसद भवन के सही हालत में होने के बावजूद सैंकड़ों करोड़ रुपये खर्च कर नया भवन बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, क्यों केन्द्र सरकार ने नया संसद भवन बनाने के नाम पर इतनी फिजूलखर्ची की तो यह बात सही है कि नई संसद के निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं, लेकिन पुराने संसद भवन में सदस्यों के बैठने के लिए सीटों की संख्या सीमित है। संसद की नई इमारत में दोनों सदनों की सीटों की संख्या को बढ़ाया गया है, ताकि भविष्य में लोकसभा और राज्यसभा में सीटें बढ़ने की स्थिति में किसी प्रकार की कोई परेशानी सामने न आए। देश में 2026 में नए सिरे से लोकसभा सीटों के परिसीमन का कार्य होने की संभावना है, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ना तय माना जा रहा है। लोकसभा में फिलहाल 545 सांसद हैं और मौजूदा लोकसभा में करीब 550 संसद सदस्यों के बैठने की ही जगह है, लेकिन परिसीमन का कार्य होने के बाद सांसदों की संख्या मौजूदा 545 से बढ़कर 700 से ज्यादा हो सकती है। इन परिस्थितियों में बड़ी सहजता के साथ यह समझा जा सकता है कि बाकी 150 से ज्यादा सांसद कहां बैठेंगे। इसी प्रकार राज्यसभा की सीटें भी परिसीमन के बाद बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि भविष्य की इन जरूरतों को पूरा करने के लिए नए भवन की जरूरत तो पड़ेगी ही, ताकि सभी सांसद सहजता से अपना कामकाज कर सकें।

पहले से होती रही है नए भवन की मांग

ब्रिटिश कालीन संसद भवन में सुविधाओं की कमी और इसके बुनियादी ढ़ांचे में खामियों को देखते हुए 13 जुलाई 2012 को कांग्रेस के शासनकाल में लोकसभाध्यक्ष मीरा कुमार ने, उसके बाद 9 दिसम्बर 2015 को सुमित्रा महाजन ने तथा 2 अगस्त 2019 को लोक सभाध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार को पत्र लिखकर नए संसद भवन का अनुरोध किया था। नए भवन का शिलान्यास करते समय प्रधानमंत्री ने इसी को रेखांकित करते हुए कहा था कि सांसद ही कई वर्षों से मांग कर रहे थे कि मौजूदा संसद भवन में उनकी जरूरतों के हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं हैं, न ही संसद भवन में सांसदों के कार्यालय हैं। समस्या यह थी कि मौजूदा संसद भवन परिसर में जगह की कमी के कारण ये तमाम व्यवस्थाएं करना संभव भी नहीं थी।

हरेक सांसद को डिजिटल तकनीक से लैस ऑफिस

नए संसद भवन में प्रत्येक सांसद को कार्यालय के लिए 40 वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। संसद की नई इमारत में राज्यसभा का आकार पहले के मुकाबले बढ़ेगा तथा लोकसभा का आकार भी मौजूदा से तीन गुना ज्यादा होगा। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक संसद की नई इमारत में प्रत्येक सांसद के लिए अलग ऑफिस होगा और हर ऑफिस सभी आधुनिक डिजिटल तकनीकों से लैस होगा। नई संसद में सांसदों के कार्यालयों को पेपरलेस ऑफिस बनाने के लिए नवीनतम डिजिटल इंटरफेस से लैस किया जा रहा है और इन दफ्तरों को अंडरग्राउंड टनल से जोड़ा जाएगा। सदन में प्रत्येक बेंच पर दो सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है और प्रत्येक सीट डिजिटल प्रणाली तथा टचस्क्रीन से सुसज्जित की गई है।

1400 सांसदों के बैठने की व्यवस्था, अनूठी है शिल्पकारी

नए भवन में कॉन्स्टीट्यूशन हॉल, सांसद लॉज, लाइब्रेरी, कमेटी रूम, भोजनालय और पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है और भवन में करीब 1400 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। नया भवन सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत मौजूदा संसद भवन के पास ही बनाया गया है, जिसके निर्माण के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को टेंडर मिला था। संसद की नई इमारत का कार्य करीब 22 माह की अवधि में पूरा होने का अनुमान था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। नए भवन की आंतरिक और बाहरी सजावट में लकड़ी का व्यापक उपयोग किया गया है और भवन की भव्यता व सुंदरता बढ़ाने के लिए इस पर बहुत सुंदर कारीगरी की गई है। इसके लिए नागपुर से मंगाई गई लकड़ी पर मुम्बई के शिल्पकारों तथा कारीगरों द्वारा खूबसूरत डिजाइन उकेरे गए हैं। नए संसद भवन को वास्तुकार बिमल पटेल के दिशा-निर्देशन में अहमदाबाद स्थित एचसीपी डिजाइन, प्लानिंग व मैनेजमेंट ने डिजाइन किया है। वास्तुविदों ने संसद के नए भवन को बनाने के लिए कई देशों की संसद का निरीक्षण कर उनसे प्रेरणा ली।

भूकंपरोधी तकनीक से बनी है इमारत, ऊर्जा-संरक्षण भी

नई संसद में रेन हार्वेस्टिंग प्रणाली तथा वाटर रिसाइक्लिंग प्रणाली के भी प्रबंध किए गए हैं। नई संसद वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त होगी और इसमें सौर प्रणाली से ऊर्जा की बचत भी होगी। तमाम सुरक्षा सुविधाओं से लैस त्रिकोणीय आकार की इस भव्य इमारत को भूकम्प रोधी तकनीक से बनाया गया है। 64500 वर्गमीटर क्षेत्र में बने नए संसद भवन में एक बेसमेंट सहित कुल चार फ्लोर हैं, जिसकी ऊंचाई संसद के मौजूदा भवन के बराबर ही है। लोकसभा कक्ष का डिजाइन राष्ट्रीय पक्षी मयूर जैसा जबकि राज्यसभा कक्ष का डिजाइन राष्ट्रीय पुष्प कमल जैसा बनाया गया है। संसद की नई इमारत में उच्चतम संरचनात्मक सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि, आधुनिक दृश्य-श्रव्य सुविधाएं, डाटा नेटवर्क प्रणाली, बैठने की आरामदायक व्यवस्था, प्रभावी और समावेशी आपातकालीन निकासी की व्यवस्थाएं भी हैं। नया संसद भवन त्रिकोणीय है, जिसका निर्माण वैदिक रीति से वास्तु के अनुसार किया गया है और यह अत्याधुनिक, तकनीकी सुविधाओं से युक्त तथा ऊर्जा कुशल भी है। कुल मिलाकर नए भवन की सज्जा में भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प एवं वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिला-जुला स्वरूप है।